

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: ०४ जुलाई, 2008

विषय:- मै0 पंतजलि आयुर्वेद लि0 द्वारा वृहद स्तर पर औषधि निर्माण एवं अनुसंधान हेतु जनपद एवं तहसील हरिद्वार के ग्राम मुस्तफाबाद में कुल 56.468 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1434/भूमि व्यवस्था-भूमि कय-VIII दिनांक 4-1-2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 पंतजलि आयुर्वेद लि0 को वृहद स्तर पर औषधि निर्माण एवं अनुसंधान हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील हरिद्वार के ग्राम मुस्तफाबाद में कुल 56.468 है0 भूमि जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये खसरा नम्बरों के अनुसार कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,

उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी तथा साथ ही भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिनों के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

7- मै0 पंतजलि आयुर्वेद लि0 द्वारा फार्मसी को औषधि लाइसेंस निर्गत किये जाने के समय वातावरण प्रदूषण एवं संरक्षण सम्बन्धी लाभ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध करायेगी।

9- इकाई द्वारा कय की जानें वाली भूमि का उपयोग "आयुर्वेदिक औषधि निर्माण तथा अनुसंधान" केन्द्र की स्थापना के लिए किया जायेगा।

10- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर किया जायेगा।

11- भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-1(10)/2001-एनईआर दिनांक 07 जनवरी, 2003 के एनेक्जर-2 में श्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत कमांक-2 तथा 12 पर उल्लिखित Medicinal Herbs & Aromatic Herbs Processing तथा फार्मा प्रोडक्ट्स गतिविधियों, जिनमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माण भी सम्मिलित है, में गतिविधियों जिनमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माण भी सम्मिलित है, में आवेदक को घोषित/ अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर भी un-notified भूमि पर विशेष पैकेज का लाभ पात्रता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

- 12- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।
- 13- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 14- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुष, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 8- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 9- निदेशक, पतंजलि आयुर्वेद लि0 कृपालुबाग, कनखल, हरिद्वार।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष/वडोनी)
अनुसचिव।